These visits are coordinated through MEA to avoid duplication and for effective presentation of our view points with the foreign Governments. Deputation abroad of officers of the level of Additional Secretary and above are scrutinized by the Screening Committee of Secretaries. The scrutiny ensures that officials are deputed abroad only when it is absolutely necessary and the matter cannot be handled by the Indian Missions abroad. The number of such deputations, the size of the delegations and the period of visits are kept to the minimum to ensure utmost economy in expenditure. Ministries Deptts. have been delegated powers to clear deputation of officials upto the level of Joint Secretary with the approval of the Minister-in-charge. On conclusion of visits, as leader of the delegation, Ministers on return from abroad are required to submit a report to the Prime Minister about the major results of the mission abroad. Similarly, officials are also required to submit reports to their Minister-in-charge/ Cabinet Secretary bringing out the achievements of such visits.

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

2780. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों/किए गए निदेशों का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बैंकों द्वारा मध्य प्रदेश में कृषि और उद्योग क्षेत्र में किए गए निवेश की राशि देश के अन्य भागों में किए गए निवेश की राशि से बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में पर्याप्त ऋण दिए जाने/निवेश किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) मार्च, 1992, मार्च, 1993 और मार्च, 1994 के अंत की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों की जिला-वार बकाया राशि विवरण में दी गयी है।

(ख) से (घ) कृषि क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों के बारे में, मार्च, 1992 को समाप्त अवधि के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश की तुलना में इन दोनों क्षेत्रों में अधिक बकाया अग्रिम राशियों वाले राज्य निम्नानुसार हैं:—

कृषि क्षेत्र	लघु उद्योग क्षेत्र
उत्तर प्रदेश	पंजाब
महाराष्ट्र	दिल्ली
आंध्र प्रदेश	पश्चिम बंगाल
कर्नाटक	उत्तर प्रदेश
तमिलनाडु	गुजरात
	महाराष्ट्र
	आन्ध्र प्रदेश
	कर्नाटक
	तमिलनाडु

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति ऊपर उल्लिखित राज्यों को छोड़कर कई राज्यों की तुलना में बेहतर है। इस संबंध में, यह कहा जा सकता है कि किसी राज्य/क्षेत्र में ऋण का अभिनियोजन आर्थिक गतिविधियों के स्तर, उद्यमवृत्ति, कच्चे माल और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, निवेश के अवसरों और उस क्षेत्र की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। अलबत्ता, बैंक ऋण के अभिनियोजन में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए बैंकों से यह कहा गया है कि वे अपनी ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं के संबंध में अखिल भारत आधार पर अलग-अलग 60% का ऋण जमा अनुपात प्राप्त करें और विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के बीच अनुपातों में व्यापक विसंगतियों को दूर करें। राज्यों में ऋण के अभिनियोजन से संबंधित मुद्दों पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में नियमित रूप से चर्चा की जाती है।

विवरण

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जिलावार बकाया अग्रिमों की राशि

(राशि लाख रु०)

जिला	मार्च, 1992	मार्च, 1993	मार्च, 1994
बालाघाट	32.83	34.06	36.00
बस्तर	46.41	45.09	36.68
बेतुल	38.53	43.74	48.08
भिंड	35.13	37.20	37.84
भोपाल	593.67	753.10	744.98
बिलासपुर	149.57	136.19	150.41
छतरपुर	30.27	32.57	33.56
छिंदवाडा	59.71	67.88	74.94
दामोह	35.33	37.30	35.70
दतिया	16.30	18.57	18.68
देवास	95.20	110.61	106.06
धार	61.38	61.97	66.74
दुर्ग	204.34	237.12	233.07
पूर्वी नीमार	96.06	99.91	102.57
गुना	63.59	65.41	72.80
ग्वालियर	282.44	297.90	315.52
होशंगाबाद	92.90	107.93	107.34
इंदौर	814.17	958.18	1078.33
जबलपुर	632.58	601.55	657.26
झबुआ	26.54	28.46	30.30
मण्डला	21.49	23.98	25.55
मंदसौर	67.21	68.51	76.27
मोरेना	74.34	81.11	83.50
नरसिंहपुर	50.70	55.08	61.55
पन्ना	13.68	15.10	15.72
रायगढ़	46.57	46.82	49.19
रायपुर	272.36	285.86	310.91
रायसीन	41.73	45.77	47.40
राजगढ़	38.17	38.50	41.51
राजनन्दगांव	43.63	41.95	41.24
रतलाम	97.69	97.89	98.73
रीवा	59.72	59.32	68.95
सागर	105.06	105.83	119.59
सतना	84.21	97.93	81.53
सिहोर	61.14	61.63	60.74
सियोनी	20.99	27.09	21.71
शाहडोल	36.79	40.46	42.97

जिला	मार्च, 1992	मार्च, 1993	मार्च, 1994
राजगढ़	48.17	48.30	44.74
शिवपुरी	33.74	35.22	39.04
सिधी	29.14	31.06	34.54
सरगुजा	31.34	31.52	31.08
टीकमगढ़	14.56	15.28	15.94
उज्जैन	224.37	230.10	177.18
विधीशा	60.41	68.81	68.76
पूर्वी नीमर	80.93	84.42	90.09

Creation of New Posts in Government Department

2781. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of new posts created in different categories under the Central Government since the introduction of economic reforms in 1991;

(b) the number of personnel recruited in different categories of posts under the Central Government since then;

(c) the amount spent on the establishment cost under the Central Government during 1981—1990;

(d) Pay allowances and all other expenses in connection with the employment of civil administrative staff;

(e) Pay allowances and all other expenses in connection with teachers, doctors engineers etc. other than with administrative duties;

(f) cost of building rent energy vehicles; and

(g) will Government lay on the Table of the House statement showing the implementation of the scheme of fully compensating dearness allowance for the employees of Central Government making it running compensation between the cost of living, wholesale price and also relevant indices with D.A. paid.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) The information on number of new posts created and personnel recruited in different categories is not centrally maintained.

(c) and (d) The expenditure on Pay and Allowances of Central Government (Civilian) regular employees during 1981—1990 was about Rs. 49985 crores.

(e) and (f) The information on pay allowance etc. of teachers, doctors, engineers etc. and cost of building, rent, energy, vehicles is not being centrally maintained.

(g) In accordance with the recommendations of IVth Central Pay Commission, as accepted by the Government Dearness Allowances is paid twice a year on the basis of percentage increase in 12 monthly average of All-India Consumer Price Index of industrial workers (General) base 1960 = 100 over the base Index 608. Central Government Employees drawing basic pay upto Rs. 3500 per month are allowed 100 per cent neutralisation, those drawing pay above Rs. 3500 and upto Rs. 6000 per month are allowed 75 per cent neutralisation and those drawing pay above Rs. 6000 per month are allowed 65 per cent neutralisation. The Report of the Fourth Pay Commission was laid on the Table of the House on 18th July, 1986.